

(2023)2 एस0सी0आर0 997

नीरज दत्ता

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)

आपराधिक अपील सं0 1669/2009

17 मार्च, 2023

(अभय एस0 ओका और राजेश बिंदल, जे0जे0)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: धारायें 7, 13(1)(डी), 13(2) - अवैध परितोषण की मांग का सबूत - अभियोजन का मामला कि एक जाल बिछाया गया था और अपीलकर्ता-बिजली निरीक्षक सह-अभियुक्तों के साथ आया और दस्तावेजों एवं 10000/- रु0 रिश्वत की मांग की गई थी जिसे शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किया गया - विशेष अदालत ने यह मानते हुए कि अपीलकर्ता के अपराध को सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे, उसे धारायें 7 और 13(i)(d)(i) और (ii) सहपठित 13(2) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा - अपील पर, माना: साक्षी सं0 5- छाया साक्षी के सबूत के अलावा, कोई अन्य सबूत नहीं है जिसे अपीलकर्ता की मांग को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा सेवा में लगाया गया है - यहां तक कि मुख्य परीक्षा में साक्षी सं0 -5 के बयानों को सही मानते हुए भी, यह अनुमान लगाना असंभव है कि 10,000/- रुपये की मांग की गई थी। अपीलकर्ता द्वारा परितोषण के माध्यम से की गई - पैसे के भुगतान के लिए की गई प्रत्येक मांग परितोषण की मांग नहीं है - इसे केवल पैसे की मांग से अधिक कुछ होना चाहिए - तथ्यों पर, अभिलेख पर ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं लाई गई हैं जो परितोषण की मांग को सिद्ध कर सकें - इस प्रकार, धारा 7 के अंतर्गत अपराध की सामग्री स्थापित नहीं हुआ परिणामस्वरूप, धारा 13(1)(डी) के अंतर्गत अपराध लागू नहीं- निचली अदालत के द्वारा पारित निर्णय को खारिज कर दिया गया।

धारायें 7, 13(1)(डी), 13(2) - अवैध परितोषण - मांग और स्वीकृति - सबूत के तरीके - अभिनिर्धारित: प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में, मांग और/या स्वीकृति को हमेशा अन्य साक्ष्यों से सिद्ध किया जा सकता है जैसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: 1.1 धारा 7 के अर्थ में मांग का प्रमाण पैसे की सरल मांग नहीं हो सकता है, बल्कि इसे कानूनी पारिश्रमिक के अलावा परितोषण की मांग होनी चाहिए। साक्षी सं0 -5 का कहना है कि जब अपीलकर्ता शिकायतकर्ता की दुकान पर गई, तो उसने शिकायतकर्ता से बिजली मीटर के संबंध में कागजात और 10,000/- रुपये देने के लिए कहा और कहा कि वह जल्दी में थी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता द्वारा छाया साक्षी की उपस्थिति में शिकायतकर्ता से

बिजली मीटर प्रदान करने के लिए परितोषण की एक विशिष्ट मांग की गई थी। साक्षी सं0 -5 ने यह नहीं बताया है कि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच उनकी उपस्थिति में कोई चर्चा हुई थी जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि अपीलकर्ता द्वारा परितोषण की मांग की गई थी। साक्षी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बीच पहले क्या हुआ था। साक्षी सं0 5 ने स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता को कथित तौर पर जिस उद्देश्य के लिए नकदी सौंपी गई थी , उसके बारे में उसे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। [कंडिका 16][1011-सी-एफ]

1.2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत अपने बयान में अपीलकर्ता के सविवरण के अनुसार, 17 अप्रैल 2000 को , वह डीवीबी कार्यालय में एलडीसी के रूप में कार्यरत थी। उस दिन, वह उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने के लिए विभाग द्वारा आयोजित एक संग्रह अभियान में अपनी आधिकारिक ड्यूटी में व्यस्त थी। उसका स्पष्टीकरण यह है कि शिकायतकर्ता उसका पड़ोसी था और वह बिजली शुल्क जमा करने के लिए उसकी सहायता चाहता था। उसने बताया कि इससे पहले उसने एक कार की खरीद-बिक्री का लेनदेन किया था शिकायतकर्ता के माध्यम से उसने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता एक हिस्ट्रीशीटर था और उसके खिलाफ तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज थीं। इस संदर्भ में साक्षी सं0-5 से जिरह में पूछताछ की गई। साक्षी सं0-5 ने सुझाव की सत्यता की पुष्टि नहीं की लेकिन कहा कि वह इससे इनकार करने की स्थिति में नहीं है। दरअसल , जांच अधिकारी साक्षी सं0-7 ने बताया कि अपीलकर्ता की कार में 71,900/- रुपये की नकदी पाई गई थी। इससे बचाव पक्ष को समर्थन मिलता है कि अपीलकर्ता द्वारा वसूली अभियान चलाया गया था। साक्षी सं0-5 के साक्ष्य के अलावा, कोई अन्य साक्ष्य नहीं है जिसे अपीलकर्ता की मांग को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा सेवा में लगाया गया हो। यहां तक की मुख्य परीक्षण में साक्षी सं0-5 के बयानों को सही मानते हुए, यह अनुमान लगाना भी असंभव है कि अपीलकर्ता द्वारा परितोषण के लिए 10,000/- रुपये की मांग की गई थी। पैसे के भुगतान के लिए की गई हर मांग परितोषण की मांग नहीं है। यह महज़ पैसे की मांग से कुछ अधिक होना चाहिए।

1.3 मृत शिकायतकर्ता द्वारा 17 अप्रैल 2000 को दायर की गई शिकायत में, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान के रूप में, उसने कहा है कि 6 मई 1996 के आवेदन के अनुसार, उसकी दुकान में एक मीटर लगाया गया था और उसके बाद कुछ महीनों बाद उन्हें पता चला कि मीटर हटा दिया गया है। हालाँकि , विशेष न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के कंडिका 19 में देखा है कि चोरी हुए बिजली मीटर के संबंध में शिकायत 25 अप्रैल 2000 को शिकायतकर्ता के कहने पर दर्ज की गई थी। इस प्रकार , चोरी हुए मीटर के संबंध में शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा 8 दिन बाद की गई थी। रिश्वत की कथित मांग. वास्तव में , साक्षी सं0 -7 ने स्वीकार

किया कि शिकायतकर्ता ने बिजली मीटर उपलब्ध कराने के लिए अपने द्वारा किए गए आवेदन की प्रति प्रस्तुत नहीं की। साक्षी सं० -7 ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि उसने ऐसा कोई आवेदन दिया है। ऐसे आवेदन देने के साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष द्वारा नया बिजली मीटर लगाने के लिए रिश्वत मांगने का मामला संदिग्ध हो जाता है। इसके अलावा, 24 अप्रैल 2000 तक शिकायतकर्ता ने अपराध घटित होने के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। इससे 17 अप्रैल 2000 को नया बिजली मीटर लगाने के लिए परितोषण की मांग के संबंध में अभियोजन पक्ष का मामला बेहद संदिग्ध हो गया है। [कंडिका 18][1012-एफ-एच; 1013-ए-बी]

1.4 अभिलेख पर ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं लाई गई है जो परितोषण की मांग को सिद्ध कर सके। इसलिए, पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध की सामग्री स्थापित नहीं की गई परिणामस्वरूप, धारा 13(1)(डी) के तहत अपराध लागू नहीं किया जाएगा। आक्षेपित निर्णय और विशेष न्यायालय के निर्णय तथा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है। [कंडिका 19,20][1013-बी-सी]

नीरज दत्ता बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) 2022 एससीसीऑनलाइन एससी 1724 - अनुसरण किया गया।

बी. जयराम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2014) 13 एससीसी 55: [2014] 4 एससीआर 554; पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम जिला पुलिस निरीक्षक, आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। (2015) 10 एससीसी 152; एम. नरसिंगा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2001) 1 एससीसी 691: [2000] 5 पूरक। एससीआर 584; एन. विजयकुमार बनाम तमिलनाडु राज्य (2021) 3 एससीसी 687 - संदर्भित। नीरज दत्ता बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) केस कानून संदर्भ [2014] 4 एससीआर 554 कंडिका 4 को संदर्भित करता है (2015) 10 एससीसी 152 कंडिका 4 में संदर्भित [2000] 5 पूरक। एससीआर 584 कंडिका 4 में संदर्भित है (2021) 3 एससीसी 687 कंडिका 11

को संदर्भित करता है, आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 1669/2009. सीआरएलए संख्या 04/2007 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 02.04.2009।

अपीलकर्ता की ओर से..... एस नागामुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सतिंदर एस गुलाटी, राज किशोर चौधरी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से..... सुश्री ऐश्वर्या भाटी, जयंत के. सूद, ए.एस.जी., श्रीकांत नीलप्पा तेरदाल, सुश्री स्निधा मेहरा, सुश्री रुख्मिणी बोबडे, संजय के.आर. त्यागी, अदित खुराना, शुभांशु पाधी, उदय

खन्ना, सुश्री पूर्णिमा सिंह , सुश्री मनीषा चावा , सुश्री बी.एल.एन.शिवानी , सुश्री शिविका मेहरा , सलाहकार।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अभय एस. ओका, जे.

तथ्यात्मक पहलू

1. अपीलकर्ता को विशेष न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 7 और धारा 13(1)(डी) के खंड (i) और (ii) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। संक्षेप में , 'पीसी अधिनियम'। सह-अभियुक्त योगेश कुमार को पीसी अधिनियम की धारा 12 के तहत दंडनीय अपराध के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराया गया था। सह-अभियुक्त को उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। अपीलकर्ता को पीसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीन साल की कठोर कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी। धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध के लिए, उसे दो साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर भी सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है।

2. शिकायतकर्ता - श्री रविजीत सिंह की सुनवाई शुरू होने से पहले ही मृत्यु हो गई। वास्तव में, साक्षी सं0 7, जांच अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता की हत्या कर दी गई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि वह नई दिल्ली के विकास पुरी स्थित एक दुकान में कारों की खरीद-फरोख्त का कारोबार करता है। उनका मामला यह है कि उनकी दुकान में कोई बिजली मीटर नहीं लगा था और इसलिए उन्होंने 6 मई 1996 को बिजली मीटर के लिए आवेदन किया था। 17 अप्रैल 2000 को उनके द्वारा दर्ज की गई शिकायत में, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए उनके बयान के रूप में , उन्होंने कहा कि 6 मई 1996 के आवेदन के अनुसार , उनकी दुकान में एक मीटर लगाया गया था और कुछ महीनों के बाद, उन्होंने पाया कि मीटर हटा दिया गया है। क्षेत्र के दुकानदारों ने अपीलकर्ता के माध्यम से बिजली मीटर लगवाए थे , इसलिए वह उनसे मिले। 17 अप्रैल 2000 को, उन्हें सुबह 7:30 बजे अपीलकर्ता से एक टेलीफोन कॉल आया , जो स्थानीय क्षेत्र में डीवीबी/बिजली विभाग में इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत था। उन्होंने बिजली मीटर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उन्हें अपने आवास पर बुलाया। सुबह 8:00 बजे, जब शिकायतकर्ता उनसे मिली, तो उन्होंने मीटर लगवाने के लिए 15,000 रुपये की मांग की और अंततः बातचीत के बाद, उन्होंने 10,000 रुपये पर तय हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार, अपीलकर्ता ने कहा कि वह दोपहर 3:00 से 4:00 बजे के बीच उसकी दुकान पर आएगी, जब शिकायतकर्ता को बिजली मीटर

के कागजात और रिश्वत के रूप में 10,000 रुपये देने होंगे। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके पास उसकी रिश्वत की मांग स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उपरोक्त शिकायत के आधार पर जाल बिछाया गया था। साक्षी सं0 5, श्री एस.के.अवस्थी, छाया साक्षी थे। जब वह शिकायतकर्ता के साथ-साथ छापेमारी दल के सदस्यों के साथ अपराहन 3:50 बजे शिकायतकर्ता की दुकान पर गए, तो अपीलकर्ता वहां मौजूद नहीं था। शाम लगभग 4:40 बजे, शिकायतकर्ता को एक टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई कि अपीलकर्ता 5:30/6:00 बजे शाम में आएगा। 5:20 बजे, अपीलकर्ता अभियुक्त के साथ आया था और दस्तावेजों और 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की, जो शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किया गया था। विशेष अदालत ने माना कि अपीलकर्ता का अपराध सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे। दरअसल, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर एक निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि मांग और स्वीकृति सिद्ध हुई थी। अपीलकर्ता के संबंध में विद्वान विशेष न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में की गई है।

4. इस अपील पर सुनवाई करते हुए, इस न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय बी. जयराम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम जिला पुलिस निरीक्षक, आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में और एम. नरसिंगा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में पहले तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के साथ विरोधाभास में थे। तदनुसार, निम्नलिखित प्रश्न बड़ी पीठ को भेजा गया:

“प्रश्न यह है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर क्या शिकायतकर्ता के साक्ष्य/अवैध परितोषण की मांग के प्रत्यक्ष या प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में, धारा 7 और धारा 13(1)(डी) सह-पठित धारा 13(1)(डी) के तहत एक लोक सेवक को दोषी/अपराध की अनुमानात्मक कटौती करने की अनुमति है? ”

"5. उपर्युक्त प्रश्न को निर्णय के लिए एक संविधान पीठ के पास भेजा गया था, जिसने 15 दिसंबर 2024 के फैसले द्वारा संदर्भ का निपटारा कर दिया। मोटे तौर पर, संविधान पीठ ने माना कि धारा 7 एवं 13(2) पीसी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के अभियोजन में शिकायतकर्ता की साक्ष्यों के अभाव में अभियोजन परितोषण को सिद्ध करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी भरोसा कर सकता है। उक्त निर्णय के कंडिका 74 में संविधान पीठ ने अपने निष्कर्षों का सारांश दिया है।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागामुथु ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता द्वारा अवैध परितोषण की मांग का कोई सबूत नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक लोक सेवक द्वारा परितोषण की मांग का प्रमाण पीसी की धारा 7 और 13 (1) (डी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि न्यायालयों के निष्कर्ष अनुमानों और अटकलों पर आधारित हैं।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने आक्षेपित निर्णयों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि साक्षी सं0 5 ने मांग को सिद्ध कर दिया है। इसके अलावा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मांग और स्वीकृति सिद्ध हुई। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार मांग और स्वीकृति स्थापित हो जाने के बाद , एक धारणा है कि परितोषण की स्वीकृति मकसद या इनाम के अस्तित्व को सिद्ध करती है। विद्वान एसजी ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णयों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

वैधानिकस्थिति

8. इससे पहले कि हम साक्ष्यों का विश्लेषण करें, हमें ध्यान देना चाहिए कि हम पीसी अधिनियम की धारा 7 और 13 से संसिमित हैं क्योंकि वे 26 जुलाई 2018 से प्रभावी 2018 के अधिनियम 16 द्वारा किए गए संशोधन से पहले मौजूद थे। हम 7 और 13 धाराओं का उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि वे अपराध के घटित होने की तिथि पर थे। धारा 7 , जैसा कि प्रासंगिक समय पर मौजूद था , इस प्रकार है:

“लोक सेवक किसी आधिकारिक कार्य के संबंध में कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य परितोषण ले रहा है। - जो कोई लोक सेवक होते हुए या होने की आशा करते हुए , अपने लिए या किसी के लिए किसी व्यक्ति से स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है अन्य व्यक्ति, कानूनी पारिश्रमिक के अलावा कोई भी परितोषण, किसी आधिकारिक कार्य को करने या न करने के लिए या दिखाने या न दिखाने के लिए, अपने आधिकारिक कार्यों के अभ्यास में , किसी व्यक्ति का पक्ष लेने या नापसंद करने के लिए एक मकसद या इनाम के रूप में। धारा 2 के खंड (सी) में निर्दिष्ट केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल या किसी स्थानीय प्राधिकरण, निगम या सरकारी कंपनी के साथ किसी भी व्यक्ति को कोई सेवा प्रदान करना या प्रदान करने का प्रयास करना। या किसी लोक सेवक के साथ, चाहे वह नामित हो या अन्यथा , कारावास से दंडनीय होगा जो छह महीने से कम नहीं होगा लेकिन जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

(स्पष्टीकरण) - (ए) "एक लोक सेवक बनने की उम्मीद"। यदि कोई व्यक्ति पद पर बने रहने की आशा नहीं रखता है, तो वह दूसरों को यह विश्वास दिलाकर धोखा देकर परितोषण प्राप्त करता है कि वह पद पर आसीन होने वाला है और फिर वह उनकी सेवा करेगा, तो वह धोखाधड़ी का दोषी हो सकता है, लेकिन वह अपराध का दोषी नहीं है। इस अनुभाग में परिभाषित किया गया है।

(बी) "परितोषण"। "परितोषण" शब्द केवल आर्थिक परितोषण या धन के रूप में अनुमानित परितोषण तक ही सीमित नहीं है।

(सी) "कानूनी पारिश्रमिक"। "कानूनी पारिश्रमिक" शब्द उस पारिश्रमिक तक ही सीमित नहीं है जिसे एक लोक सेवक कानूनी रूप से मांग सकता है, बल्कि इसमें वे सभी पारिश्रमिक शामिल हैं जिन्हें स्वीकार करने के लिए उसे सरकार या संगठन द्वारा अनुमति दी गई है, जिसकी वह सेवा करता है।

(डी) "करने का एक उद्देश्य या पूर्ति"। एक व्यक्ति जो प्रेरणा के लिए काम कर रहा है या पुरस्कार के रूप में परितोषण प्राप्त कर रहा है, उसका जो इरादा नहीं है या करने की स्थिति में नहीं है, या नहीं किया गया है, इस अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है।

(इ) जहां एक लोक सेवक किसी व्यक्ति को गलती से यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि सरकार के साथ उसके प्रभाव ने उस व्यक्ति के लिए एक डिग्री प्राप्त कर ली है और इस प्रकार उस व्यक्ति को इस सेवा के लिए पुरस्कार के रूप में दिया जाता है लोक सेवक में, धन या किसी अन्य परितोषण के लिए प्रेरित किया जाता है, तो लोक सेवक ने इस धारा के तहत अपराध किया है।”

9. धारा 13(1)(डी), जैसा कि प्रासंगिक समय पर मौजूद था, इस प्रकार है:

“13. एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार।- (1) एक लोक सेवक के बारे में कहा जाता है कि वह आपराधिक कदाचार का अपराध करता है,

(ए)

(बी)

(सी)

(डी) यदि वह,

(i) भ्रष्ट या अवैध तरीकों से, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

(ii) लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

(iii) एक लोक सेवक के रूप में पद पर रहते हुए , बिना किसी सार्वजनिक हित के किसी भी व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

(इ)।"

परितोषण की मांग और उसकी स्वीकृति पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अनिवार्य है।

10. जिस प्रश्न का हमने पहले हवाला दिया है, वह निर्णय हेतु संविधान पीठ के समक्ष था। कंडिका 74 में, संविधान के निष्कर्षों का सारांश दिया गया है, जो इस प्रकार है:

“74. उपरोक्त चर्चा से जो उभर कर सामने आता है उसका सारांश इस प्रकार है:

(ए) अधिनियम के धारा 7 और 13(1)(डी) (i) और (ii) के तहत आरोपी लोक सेवक के अपराध को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा एक तथ्य के रूप में एक लोक सेवक द्वारा अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति का प्रमाण एक अनिवार्य शर्त है।

(बी) अभियुक्त के अपराध को सामने लाने के लिए , अभियोजन पक्ष को पहले अवैध परितोषण की मांग और उसके बाद की स्वीकृति को तथ्य के रूप में सिद्ध करना होगा। इस मुद्दे में तथ्य को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है जो मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य की प्रकृति में हो सकता है।

(सी) इसके अलावा , मुद्दे में तथ्य , अर्थात् मांग का प्रमाण और अवैध परितोषण की स्वीकृति को प्रत्यक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है।

(डी) मामले में तथ्य को सिद्ध करने के लिए, अर्थात्, लोक सेवक द्वारा अवैध परितोषण की मांग और स्वीकार करना, निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना होगा:

(i) यदि रिश्वत देने वाले द्वारा लोक सेवक से कोई मांग किए बिना भुगतान करने की पेशकश की जाती है और बाद वाला केवल प्रस्ताव स्वीकार करता है और अवैध परितोषण प्राप्त करता है, तो यह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार स्वीकृति का मामला है। ऐसे मामले में , लोक सेवक द्वारा पूर्व मांग की आवश्यकता नहीं है।

(ii) दूसरी ओर, यदि लोक सेवक मांग करता है और रिश्वत देने वाला मांग स्वीकार कर लेता है और मांगी गई परितोषण प्रदान करता है जो बदले में लोक सेवक को प्राप्त होती है , तो यह प्राप्ति का मामला है। प्राप्ति के मामले में, अवैध परितोषण की पूर्व मांग लोक सेवक से उत्पन्न होती है। यह अधिनियम की धारा 13(1)(डी)(i) और (ii) के तहत अपराध है ।

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) दोनों मामलों में, रिश्वत देने वाले की पेशकश और लोक सेवक की मांग को क्रमशः अभियोजन पक्ष द्वारा एक तथ्य के रूप में सिद्ध करना होगा। दूसरे शब्दों में, किसी अवैध परितोषण को बिना अधिक कुछ स्वीकार या प्राप्त करना इसे क्रमशः अधिनियम की धारा 7 या धारा 13(1)(डी), (i) और (ii) के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। इसलिए, अधिनियम की धारा 7 के तहत, अपराध को अंजाम देने के लिए , एक प्रस्ताव होना चाहिए जो रिश्वत देने वाले से आता है जिसे लोक सेवक द्वारा स्वीकार किया जाता है जो इसे अपराध बना देगा । इसी प्रकार, लोक सेवक द्वारा की गई पूर्व मांग , जब रिश्वत देने वाले द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं एवं बदले में भुगतान किया जाता है, जो लोक सेवक द्वारा प्राप्त किया जाता है, अधिनियम के धारा 13(1) (डी) (i) और (ii) के तहत प्राप्ति का अपराध होगा।

(इ) अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति या प्राप्ति के संबंध में तथ्य की धारणा कानून की अदालत द्वारा केवल एक अनुमान के माध्यम से की जा सकती है जब मूलभूत तथ्य प्रासंगिक मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा सिद्ध किए गए हों, न कि उसका अभाव अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर, न्यायालय के पास यह विचार करते समय तथ्य की एक धारणा बनाने का विवेक है कि क्या मांग का तथ्य अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध किया गया है या नहीं। निःसंदेह, तथ्य की एक धारणा अभियुक्त द्वारा खंडन के अधीन है और खंडन के अभाव में धारणा कायम रहती है।

(एफ) यदि शिकायतकर्ता 'पक्षद्रोही' हो जाता है , या उसकी मृत्यु हो गई है या मुकदमे के दौरान अपने साक्ष्य देने के लिए अनुपलब्ध है , तो किसी अन्य गवाह के साक्ष्य को देकर अवैध परितोषण की मांग को सिद्ध किया जा सकता है, जो फिर से साक्ष्य दे सकता है। या तो मौखिक रूप से या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा या अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा मामले को सिद्ध कर सकता है। मुकदमा समाप्त नहीं होता है और न ही इसके परिणामस्वरूप आरोपी लोक सेवक को दोषमुक्त करने का आदेश मिलता है।

(जी) जहां तक अधिनियम की धारा 7 का प्रश्न है, मुद्दे में तथ्यों के प्रमाण पर, धारा 20 अदालत को यह अनुमान लगाने का आदेश देती है कि अवैध परितोषण किसी मकसद या इनाम के उद्देश्य से था जैसा कि उक्त धारा में उल्लिखित है। उक्त अनुमान को अदालत द्वारा कानूनी

अनुमान या कानून में अनुमान के रूप में उठाया जाना चाहिए। बेशक , उपरोक्त अनुमान भी खंडन के अधीन है। धारा 20 अधिनियम की धारा 13(1)(डी) (i) और (ii) पर लागू नहीं होती है।

(एज) हम स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम की धारा 20 के तहत कानून में अनुमान ऊपर बताए गए तथ्य की धारणा से अलग है

(ई) चूंकि पूर्व एक अनिवार्य अनुमान है जबकि बाद वाला विवेकाधीन है।

संदर्भित प्रश्न का उत्तर उपरोक्त निर्णय के कंडिका 76 में दिया गया था, जो इस प्रकार है:

“76. तदनुसार, इस संविधान पीठ के विचारार्थ संदर्भित प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया है:

शिकायतकर्ता के साक्ष्य (प्रत्यक्ष/प्राथमिक , मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य) के अभाव में , धारा 7 और धारा 13(1)(डी) के तहत एक सर्वजनिक सेवक दोषी/अपराध की अनुमानात्मक कटौती करने की अनुमति है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आधार पर अधिनियम की धारा 13(2) पठित धारा के तहत एक लोक सेवक के दोषी/अपराध की अनुमानात्मक कटौती करने की अनुमति है।

11. यहां तक कि पीसी अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान के मुद्दे का भी संविधान पीठ ने यह कहते हुए उत्तर दिया है कि केवल मुद्दे में तथ्यों के प्रमाण पर , धारा 20 न्यायालय को यह अनुमान लगाने का आदेश देती है कि अवैध परितोषण किस प्रयोजन के लिए था मकसद या इनाम जैसा कि धारा 7 में उल्लिखित है (जैसा कि यह 2018 के संशोधन से पहले मौजूद था)। दरअसल, संविधान पीठ ने बी जयराज और पी. सत्यनारायण मूर्ति के मामले में तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ के दो फैसलों को मंजूरी दे दी है । एक अन्य मामले में तीन जजों की पीठ का एक और फैसला है विजयकुमार बनाम तमिलनाडु राज्य , जो बी. जयराज और पी. सत्यनारायण मूर्ति के मामलों में अपनाए गए दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। बी. जयराज के मामले में निर्णय के कंडिका 9 में, इस न्यायालय ने पीसी अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान को सुलझाया है। कंडिका 9 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

“9. जहां तक अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान लगाने की अनुमति का सवाल है , ऐसी धारणा केवल धारा 7 के तहत अपराध के संबंध में हो सकती है , न कि धारा 13(1)(डी)(i) और (ii) के तहत अपराधों के संबंध में। अधिनियम का किसी भी घटना में , केवल अवैध परितुष्टि की स्वीकृति के प्रमाण पर ही अधिनियम की धारा 20 के तहत यह धारणा बनाई जा सकती है कि ऐसी परितोषण किसी आधिकारिक कार्य को करने या न करने के लिए प्राप्त की गई थी। अवैध परितोषण की स्वीकृति का प्रमाण तभी मिल सकता है जब मांग का प्रमाण हो। चूंकि वर्तमान

मामले में इसकी कमी है , इसलिए प्राथमिक तथ्य जिनके आधार पर धारा 20 के तहत कानूनी अनुमान लगाया जा सकता है, पूरी तरह से अनुपस्थित हैं।

धारा 20 के तहत अनुमान केवल तभी लागू किया जा सकता है जब धारा 7 के तहत सिद्ध करने के लिए आवश्यक दो बुनियादी तथ्य सिद्ध हो जाएं। उक्त दो मूल तथ्य हैं परितोषण की 'मांग' और 'स्वीकृति'। धारा 20 के तहत धारणा यह है कि जब तक कि विपरीत सिद्ध न हो जाए , परितोषण की स्वीकृति एक मकसद या इनाम के लिए मानी जाएगी , जैसा कि धारा 7 में विचार किया गया है। इसका मतलब यह है कि एक बार अवैध परितोषण की मांग और उसकी स्वीकृति के बुनियादी तथ्य सिद्ध हो जाते हैं, जब तक कि विपरीत सिद्ध न हो जाए, अदालत को यह मानना होगा कि परितोषण की मांग की गई थी और उसे धारा 7 के अनुसार एक मकसद या इनाम के रूप में स्वीकार किया गया था। हालाँकि, यह अनुमान खंडनयोग्य है। संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर भी अभियुक्त अनुमान का खंडन कर सकता है।

12. एन. विजयकुमार के मामले में, तीन माननीय न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ ने धारा 20 के तहत अनुमान के मुद्दे और धारा 7 और खंड (i) और (ii) के तहत दंडनीय अपराधों को स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत की स्तर पर विचार किया। धारा 13(1)(डी) पीसी अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित। कंडिका 26 में, पीठ ने इस प्रकार कहा:

“26. यह भी समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि केवल बरामदगी ही अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन के आरोप को सिद्ध नहीं कर सकती है। सीएम गिरीश बाबू बनाम सीबीआई और बी. जयराम बनाम राज्य में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है। जयराम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य , (2014) 13 एससीसी 55: (2014) 5 एससीसी (सीआरआई) 543] भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम , 1988 के धारा 7 , 13(1)(डी)(आई) और (ii) तहत मामले पर विचार करते हुए इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में के तहत यह दोहराया जाता है कि आरोप को सिद्ध करने के लिए, बिना किसी संदेह के यह सिद्ध करना होगा कि अभियुक्त ने यह जानते हुए कि यह रिश्वत है स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए। अवैध परितोषण की मांग के सबूत का अभाव और केवल करेंसी नोटों का कब्जा या बरामदगी ऐसे अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उक्त निर्णयों में यह भी माना गया है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत भी अनुमान अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति सिद्ध होने के बाद ही लगाया जा सकता है। यह भी काफी हद तक स्थापित है कि आपराधिक न्यायशास्त्र में निर्दोषता की प्रारंभिक धारणा विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति होने से दोगुनी हो जाती है। इस प्रकार, परितोषण की मांग और उसकी स्वीकृति उचित संदेह से परे सिद्ध होनी चाहिए।

13. धारा 7 , जैसा कि 26 जुलाई 2018 से पहले अस्तित्व में थी , वर्तमान धारा 7 से अलग थी । असंशोधित धारा 7 जो वर्तमान मामले में लागू है, विशेष रूप से "किसी भी परितोषण" को संदर्भित करती है। प्रतिस्थापित धारा 7 में "परितोषण" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है , बल्कि यह एक व्यापक शब्द "अनुचित लाभ" का उपयोग करता है। जब आरोप अभियुक्त द्वारा परितोषण की मांग और उसे स्वीकार करने का है , तो यह किसी आधिकारिक कार्य को करने या न करने के मकसद या इनाम के रूप में होना चाहिए। तथ्य यह है कि परितोषण की मांग और स्वीकृति मकसद या इनाम के लिए थी, जैसा कि धारा 7 में प्रदान किया गया है , धारा 20 के तहत अनुमान लागू करके सिद्ध किया जा सकता है , बशर्ते मांग और स्वीकृति के मूल आरोप सिद्ध हों। इस मामले में, हम खंड (i) और (ii) धारा 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध से भी संबद्ध हैं जो पीसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दंडनीय है। धारा 13 की उपधारा (1) का खंड (डी) , जो 26 जुलाई 2018 के संशोधन से पहले कानून की किताब में मौजूद था , पहले उद्धृत किया गया है। धारा 13(1)(डी) के खंड (i) और (ii) को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर , यह स्पष्ट है कि खंड (i) और (ii) के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए अवैध परितोषण की स्वीकृति का प्रमाण आवश्यक होगा। धारा 13(1)(डी) संविधान पीठ द्वारा तय की गई बातों के मद्देनजर , किसी दिए गए मामले में , एक लोक सेवक द्वारा अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति को प्रत्यक्ष मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। संदर्भित प्रश्न का उत्तर देते समय , संविधान पीठ ने कहा कि धारा 13(2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 7 और 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए लोक सेवक की दोषीता और/या अपराध की अनुमानात्मक कटौती करने की अनुमति है। पीसी अधिनियम का निष्कर्ष यह है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में, मांग और/या स्वीकृति को हमेशा परिस्थितिजन्य साक्ष्य जैसे अन्य साक्ष्यों से सिद्ध किया जा सकता है।

14. एक लोक सेवक द्वारा परितोषण और स्वीकृति की मांग के आरोप को उचित संदेह से परे स्थापित किया जाना चाहिए। संविधान पीठ का निर्णय उचित संदेह से परे सबूत कि इस मौखिक सिद्धांत को कमजोर नहीं करता है। संविधान पीठ उन तरीकों के मुद्दे पर विचार कर रही थी जिनके द्वारा मांग को सिद्ध किया जा सकता है। संविधान पीठ ने कहा है कि सबूत के लिए केवल प्रत्यक्ष मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है , बल्कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य सहित अन्य साक्ष्य के माध्यम से भी हो सकता है। जब परितोषण की मांग को सिद्ध करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है , तो अभियोजन पक्ष को प्रत्येक परिस्थिति को स्थापित करना होगा, जिससे अभियोजन पक्ष चाहता है कि अदालत अपराध का निष्कर्ष निकाले। इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल एक परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए कि अभियुक्त द्वारा परितोषण की मांग की गई थी। इसलिए , इस मामले में, हमें यह जांचना होगा कि मांग का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है या नहीं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मांग का

कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तो इस न्यायालय को इस पर विचार करना होगा कि क्या मांग को सिद्ध करने के लिए कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार

15. अब, अभिलेख पर साक्ष्य की बात करें तो अभियोजन पक्ष के अनुसार , प्रत्यक्ष साक्ष्य साक्षी सं0 5 - श्री एस.के.अवस्थी, साक्ष्य के रूप में है। इस मामले में, शिकायतकर्ता की मृत्यु हो गई थी और इसलिए, उससे पूछताछ नहीं की जा सकी। छापेमारी दल में साक्षी सं0 5, श्री एस.के.अवस्थी, सिंचाई विभाग के एक अधिकारी थे ; साक्षी सं0 6, श्री ओडी यादव, यातायात निरीक्षक और साक्षी सं0 7, श्री निरंजन सिंह, एसीपी। परिवाद, जिसे शिकायतकर्ता के माध्यम से सिद्ध नहीं किया जा सका, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता से पहली मांग 17 अप्रैल 2000 की सुबह की थी जब वह उससे उसके आवास पर मिला था। इस मांग के आधार पर कोई आरोप तय नहीं किया गया. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, दूसरी मांग ट्रैप के दौरान की गई थी। अपीलकर्ता के घर में की गई पहली मांग के बारे में कोई सबूत नहीं है क्योंकि शिकायतकर्ता के अलावा कोई भी वहां मौजूद नहीं था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार , साक्षी सं0 5, 17 अप्रैल 2000 को शाम लगभग 5:20 बजे अपीलकर्ता द्वारा की गई दूसरी मांग का गवाह था, साक्षी सं0 5 ने अपने साक्ष्य में कहा कि हालांकि शिकायतकर्ता ने ट्रैप पार्टी को सूचित किया था कि अपीलकर्ता उसके पास आएगा लगभग 3:50 बजे दुकान पर अपीलकर्ता नहीं आया। इसके बाद, शिकायतकर्ता को एक टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि वह शाम 5:30/6:00 बजे तक आएगी। अंततः , साक्षी सं0 5 के मामले के अनुसार , लगभग 5:20 बजे, अपीलकर्ता सहअभियुक्तों के साथ शिकायतकर्ता के दुकान पर पास आई। साक्षी सं0 5 का संस्करण, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार मांग का गठन करता है, इस प्रकार है:

"श्रीमती नीरज दत्ता ने शिकायतकर्ता से अपने बिजली मीटर के कागजात और 10,000 रुपये देने के लिए कहा क्योंकि वह जल्दी में थी। शिकायतकर्ता ने अपने बिजली मीटर के दस्तावेज और 10,000 रुपये के जीसी नोट अपनी शर्ट की बाईं जेब से निकालकर श्रीमती नीरज दत्ता को उनके दाहिने हाथ में सौंप दिए। श्रीमती नीरज दत्ता ने उक्त जीसी नोट्स को अपने सहयोगी योगेश कुमार को गिनने के लिए सौंप दिया और उन्होंने शिकायतकर्ता से कहा कि उनका काम हो जाएगा।

16. शेष परीक्षण मुख्य अपीलकर्ता द्वारा स्वीकृति और वसूली से संबंधित है। अब सवाल यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने अभिलेख पर मौजूद सबूतों के आधार पर आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग को सिद्ध कर दिया है। जब हम धारा 7 के अर्थ में मांग के सबूत के मुद्दे पर विचार करते हैं , तो यह पैसे की एक सरल मांग नहीं हो सकती है , लेकिन इसे कानूनी पारिश्रमिक के अलावा परितोषण की मांग होनी चाहिए। साक्षी सं0 5 का कहना है कि जब अपीलकर्ता शिकायतकर्ता की दुकान पर गई , तो उसने शिकायतकर्ता को यह कहकर बिजली मीटर और 10,000 रुपये के

कागजात देने के लिए कहा कि वह जल्दी में थी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता द्वारा छाया गवाह की उपस्थिति में शिकायतकर्ता से बिजली मीटर प्रदान करने के लिए परितोषण की एक विशिष्ट मांग की गई थी। साक्षी सं0 5 ने यह नहीं बताया है कि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच उनकी उपस्थिति में कोई चर्चा हुई थी जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि अपीलकर्ता द्वारा परितोषण की मांग की गई थी। गवाह को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बीच पहले क्या हुआ था। साक्षी सं0 5 ने स्वीकार किया कि उस उद्देश्य के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी जिसके लिए की नकदी कथित तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता को सौंपी गई थी।

17. हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता के बयान के अनुसार, 17 अप्रैल 2000 को, वह डीवीबी कार्यालय में एलडीसी के रूप में काम कर रही थी। उस दिन, वह उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने के लिए विभाग द्वारा आयोजित एक संग्रह अभियान में अपनी आधिकारिक ड्यूटी में व्यस्त थी। उसका स्पष्टीकरण यह है कि शिकायतकर्ता उसका पड़ोसी था और वह बिजली शुल्क जमा करने के लिए उसकी सहायता चाहता था। उसने कहा कि पहले उसने शिकायतकर्ता के माध्यम से एक कार की बिक्री और खरीद का लेनदेन किया था। उसने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता एक हिस्ट्रीशीटर था और उसके खिलाफ तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज थीं। इस संदर्भ में, साक्षी सं0 5 से जिरह में पूछताछ की गई। साक्षी सं0 5 द्वारा दिया गया प्रासंगिक उत्तर इस प्रकार है:

“मैं इस बात की पुष्टि या खंडन नहीं कर सकता कि आरोपी नीरज दत्ता ने अपने कैशियर और चार पांच सदस्यों वाले अन्य स्टाफ के साथ मिलकर जय विहार में आयोजित सिंगल डिलीवरी पॉइंट कैंप में 71,000 रुपये एकत्र किए थे और वह अपने स्टाफ सदस्यों के साथ अपनी कार में आ रही थीं और रास्ते में वह शिकायतकर्ता की दुकान पर रुकी, जो कि शिकायतकर्ता की पड़ोसी थी, उसकी पिछली कार की शेष बिक्री राशि 1 लाख रुपये लेने के लिए क्योंकि उसने उक्त कार को मैसर्स को शिकायतकर्ता के द्वारा बेच दिया था और यह भुगतान उसे शिकायतकर्ता के माध्यम से मैसर्स सागर मोटर्स से प्राप्त होना था।” यहां यह ध्यान रखना उचित है कि साक्षी सं0 5 ने सुझाव की सत्यता की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा है कि वह इससे इनकार करने की स्थिति में नहीं है। दरअसल, जांच अधिकारी साक्षी सं0 7 ने बताया कि अपीलकर्ता की कार में 71,900 रुपये की नकदी पाई गई थी। इससे बचाव पक्ष को समर्थन मिलता है कि अपीलकर्ता द्वारा वसूली अभियान चलाया गया था। साक्षी सं0 5 के साक्ष्य के अलावा, कोई अन्य साक्ष्य नहीं है जिसे अपीलकर्ता की मांग को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा सेवा में लगाया गया हो। यहां तक कि मुख्य परीक्षण में साक्षी सं0 5 के बयानों को सही मानते हुए भी, यह अनुमान लगाना असंभव है कि अपीलकर्ता द्वारा परितोषण के तौर पर 10,000 रुपये की मांग की गई थी।

पैसे के भुगतान के लिए की गई हर मांग परितोषण की मांग नहीं है। यह महज़ पैसे की मांग से कुछ अधिक होना चाहिए।

18. ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण तथ्यात्मक पहलू है जो अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा करता है। मृत शिकायतकर्ता द्वारा 17 अप्रैल 2000 को दायर की गई शिकायत में, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान के रूप में, उन्होंने कहा है कि 6 मई 1996 के आवेदन के अनुसार, एक मीटर उसकी दुकान में स्थापित किया गया था और कुछ महीनों के बाद, उसने पाया कि मीटर हटा दिया गया था। हालाँकि, विशेष न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के कंडिका 19 में देखा है कि चोरी हुए बिजली मीटर के संबंध में शिकायत 25 अप्रैल 2000 को शिकायतकर्ता के कहने पर दर्ज की गई थी। इस प्रकार, चोरी हुए मीटर के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा 8 दिन बाद शिकायत की गई थी। रिश्वत की कथित मांग. वास्तव में, साक्षी सं0 7 ने स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता ने बिजली मीटर उपलब्ध कराने के लिए उसके द्वारा किए गए आवेदन की एक प्रति प्रस्तुत नहीं की। साक्षी सं0 7 ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने उसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि उसने ऐसा आवेदन दिया था। ऐसे आवेदन देने के साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष द्वारा नया बिजली मीटर लगाने के लिए रिश्वत मांगने का मामला संदिग्ध हो जाता है। इसके अलावा, 24 अप्रैल 2000 तक शिकायतकर्ता ने अपराध घटित होने के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। इससे 17 अप्रैल 2000 को नया बिजली मीटर लगाने के लिए परितोषण की मांग के संबंध में अभियोजन पक्ष का मामला बेहद संदिग्ध हो गया है।

19. वर्तमान मामले में, ऐसी कोई परिस्थिति अभिलेख पर नहीं लाई गई है जो परितोषण की मांग को सिद्ध करेगी। इसलिए, पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध की सामग्री स्थापित नहीं की गई और परिणामस्वरूप, धारा 13(1)(डी) के तहत अपराध लागू नहीं किया जाएगा।

20. इसलिए, अपील स्वीकृत होनी चाहिए। हम आक्षेपित निर्णय और विशेष न्यायालय के फैसले को निरस्त करते हैं और अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा भी रद्द करते हैं। अपीलकर्ता के जमानत प्रतिभू रद्द किये जाते हैं। अपील स्वीकृत की जाती है।

रंजीत कुमार

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जामताड़ा